यूपीए सरकार का तीसरा बजट

ग़रीबों की दुहाई और अमीरों को मलाई

● अजय, पवन

हाल ही में यूपीए सरकार का तीसरा बजट पास हुआ। इसे पेश करते हुए पी. चिदम्बरम ने कहा कि 'हमारी सरकार एक दयालु सरकार है' और इसमें 'आम आदमी' शब्द कम-से-कम 45 से 50 बार आया होगा। लेकिन बजट के एक हल्के विश्लेषण से ही यह बात समझ में आ जाती है कि बजट में आम आदमी की दुहाई चाहे जितनी भी दी गई हो इसमें भूमण्डलीकरण की उसी प्रक्रिया को व्यवस्थित ढँग से आगे बढ़ाया गया है, जो आम आदमी को तबाह कर रही है।

भूमण्डलीकरण को बहुत तेज़ करने वाला कोई कदम पूँजीपतियों के काबिल मुनीम चिदम्बरम ने नहीं उठाया है। कारण यह था कि उस समय तक केरल और बंगाल के चुनाव नहीं बीते थे। आख़िर संसदीय वामपंथी शेखचिल्लियों को भी तो मुँह दिखाने लायक छोड़ना था! नतीजतन, इस बार के बजट में आयकर और निगम कर ढाँचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। छह में से एक चीज़ रखने वालों के आयकर रिटर्न भरने की अनिवार्यता को भी ख़त्म कर दिया गया। मतलब मध्यम वर्ग की भी बल्ले-बल्ले और पूँजीपतियों की भी! इससे बंगाल और केरल के चुनाव में वामपंथियों को ख़ास फ़ायदा मिला। वहाँ का पढ़ा-लिखा शहरी मध्यवर्ग इस लॉलीपॉप को चूसते-चूसते अपनी चहेती पार्टी को वोट दे आया। इस बार किसी बड़े विनिवेश की भी घोषणा नहीं हुई। साथ ही श्रम कानूनों में बदलाव को भी चिदम्बरम अभी टाल गए। इससे संगठित क्षेत्र के मज़दूरों का गुस्सा क़ाबू में रहेगा और उनका वोट संसदीय बात-बहादुरों को मिल जाएगा।

लेकिन जिस ग़रीब की दुहाई बार-बार दी गई है वास्तव में उसके लिए सरकार ने क्या किया है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार योजना, सर्वशिक्षा अभियान, मिड डे मील आदि, जिसका कोई विशेष लाभ ग़रीबों तक नहीं पहुँच पाता है और अगर बहुत छूट देकर, उदारता के साथ सोचा जाय तो उन्हें यही कहा जा सकता है—असामान्यतः अपर्याप्त! राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार योजना के मद में 14300 करोड़ रुपये आबण्टित किये गए हैं। लेकिन वहीं सम्पूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना पर खर्च में 4950 करोड़ रुपये की कटौती की गई है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम को पूरी तरह बन्द कर दिया गया है यानी कि 4050 करोड़ रुपये की कटौती। यानी खर्चों में कुल कटौती 9000 करोड़ रुपये। इस प्रकार राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार योजना पर ख़र्च 10170 करोड़ बढ़ाया गया तो चोर दरवाज़े से 9000 करोड़ रुपये का ख़र्च कम कर दिया गया। वहीं यह योजना लागू होते ही देश के 200 जिलों में लगभग 77 लाख लोगों ने आवेदन किया। खुद सरकार के अनुसार यह असली संख्या का केवल 40 प्रतिशत है। यानी आने वाले दिनों में यह संख्या 2 करोड़ तक पहुँच सकती है। अब 14300 करोड़ रुपये में 2 करोड़ लोगों को साल भर में 100 दिन का रोज़गार कैसे मिलेगा, यह बात या तो अल्ला मियाँ जानते हैं या मक्कार मुनीम चिदम्बरम! इस योजना को सफल बनाने के लिए मोटे तौर पर 25 से 30 हज़ार करोड़ रुपये की ज़रूरत पड़ेगी।

दरअसल, चिदम्बरम महोदय की पूरी चिन्ता के केन्द्र में था बजट घाटा और वित्तीय घाटा कम करना। बजट घाटे को जीडीपी के 2.1 प्रतिशत और वित्तीय घाटे को जीडीपी के 3.8 प्रतिशत तक लाने के लिए श्रीमान मुनीम को पूँजीपतियों की शाबाशी भी खूब मिली। लेकिन यह सम्भव कैसे हुआ है? जाहिर है खर्चे कम करके। किन मदों में? सार्वजनिक क्षेत्र में किये जाने वाले निवेश के मद में। यानी वे मद जिनसे आम आदमी को राहत मिलती है, जैसे सरकारी अस्पताल, स्कूल, आदि, उनमें कटौती करके और दो-तीन चीज़ों को करों के दायरे में लाकर बजट घाटे को कम करने की कवायद की गई है। ये तो गज़ब का आम आदमी का बजट है!!

साथ ही चिदम्बरम मुनीम ने आम आदमी पर क्या-क्या अहसान किये हैं, सुनिये। छोटी कारें, कोल्ड ड्रिंक, 250-750 रुपये तक के जूते आदि सस्ते होंगे। अब कौन सा आम आदमी मारूती ख़रीदता है यह तो मुनीम जी ही बता सकते हैं। हाँ, कुछ लोग खाए-पिये मध्यम वर्ग को ही आम आदमी मानते हैं। उसके नीचे के लोगों के लिए शायद वे किसी नयी संज्ञा के आविष्कार में लगे हुए हैं! यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों के 25-30 हज़ार पाने वाले प्रोफेसर, मध्यम दर्जे के सरकारी नौकरशाह आदि भी रामजाने किस पैमाने से अपने आपको "आम आदमी" मानते हैं! बहरहाल, अगर आम आदमी यही हैं, तब तो मुनीम जी ने वाकई इनके लिए ख़ैराती खाता खोल दिया है! लेकिन शायद हिन्दी भाषा के सीमित ज्ञान के कारण या राजनीतिक नादानी के कारण इस टिप्पणी का लेखक आज तक यह समझता आया था कि आम आदमी का मतलब होता है मेहनतक़श आबादी, निम्न मध्य वर्ग, किसान और मज़दूर आबादी!!

आम आदमी का नाम लेकर चिदम्बरम ने सेवा किसकी की है? जवाब साफ़ है—पूँजीपतियों की। अनेक गैर कृषि उत्पादों पर से आयात शुल्क 16 प्रतिशत से घटाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया गया। इससे देशी पूँजी को विदेशी मालों से जो प्रतिस्पर्द्धा झेलनी पड़ेगी उससे तो वह दुखी है लेकिन पूँजीगत मालों से सस्ते होने से वह अपने उद्योगों को और तेज़ी से आधुनिकीकृत कर पाएगी, इसकी खुशी उसे कहीं ज्यादा है। बड़े पूँजीपतियों के लिए रास्ता और साफ़ करने के लिए 180 और वस्तुओं को लघु उद्योगों के लिए आरक्षित सूची से बाहर कर दिया है। इसकी एवज़ में उनके कर्ज़ों में थोड़ी कटौती करने की बात कही गई है, लेकिन कहने की ज़रूरत नहीं कि इससे लघु उद्योगों का बच पाना सम्भव नहीं है और पूँजीवाद का वही जंगल राज यहाँ चलेगा—बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है।